

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1421

जिसका उत्तर मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

विद्युत मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय मिशन

1421. श्री रामसिंह राठवा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक और भारी वाहनों के लिए निर्धारित चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से विश्वसनीय इलेक्ट्रीसिटी पहुंच प्रदान करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;
- (ख) क्या पर्यावरण संरक्षण और CO2 को कम करने के संदर्भ में वास्तविक लाभ तभी होंगे जब इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से चार्ज किया जाएगा, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा सशक्त मिशन के अंतर्गत चार्जिंग का कतिपय प्रतिशत बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने की योजना है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)**

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन वर्ष 2011 में अनुमोदित किया और तत्पश्चात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 वर्ष 2013 में अनावृत्त किया था। मिशन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने **फेम-इंडिया** (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) नाम की स्कीम तैयार की है। स्कीम का चरण-1 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर 2 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ₹795 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। ₹75 करोड़ की प्रारंभिक राशि चालू वित्त वर्ष (2015-16) में आबंटित कर दी गई है। स्कीम के चार फोकस क्षेत्र होंगे यथा प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्ज करने संबंधी बुनियादी ढांचा। इस स्कीम के माध्यम से सरकार का बल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदारों की प्रथम पसंद बनाने पर होगा ताकि ये वाहन परम्परागत वाहनों को प्रतिस्थापित कर सकें और ऑटोमोबाइल सेक्टर से देश में तरल ईंधन खपत में कमी आ सके।

(ख) और (ग): यह स्कीम देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, दोनों प्रौद्योगिकियों के व्यवहार्य इको-सिस्टम (पारिस्थितिकी-तंत्र) के सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सरकार ऐसे विभिन्न शहरों जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर रही है। सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), तेल तथा विपणन कंपनियां (जैसे इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) जैसी समर्थकारी विभिन्न एजेन्सियों के साथ उनके सुविधा स्थलों (मेट्रो स्टेशनों और पेट्रोल स्टेशनों) पर ऐसे चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने की सहायता हेतु समन्वय कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित तीव्र चार्जिंग स्टेशनों की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) तथा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) को ऐसे स्टेशनों के प्रोटोटाइप्स विकसित करने का कार्य सौंपा गया है जो भविष्य में स्थापित किए जा सकें।

इस तथ्य के आधार पर कि अधिकांश उत्पादित विद्युत मुख्यतः कोल, प्राकृतिक गैस और तेल (75%-85%) से प्राप्त होती है, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में समकक्ष गैसोलीन वाहन की तुलना में लगभग 35%-45% कम CO2 उत्पन्न करते हैं। भविष्य में देश में ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक वाहन वेल-टू-व्हील आधार पर CO2 का कम उत्सर्जन करेंगे।

(घ): प्रश्न नहीं उठाता।
